2017-18 का बजट और नाबार्ड - ग्रामीण सहकारी बैंक

केंद्रीय बजट में भारत की ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के सबसे निचले स्तर अर्थात् प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों तक डिजिटल बैंकिंग को पहुंचाने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए रु.1,900 करोड़ का आबंटन किया गया है. इस आबंटन से 63,000 समितियां जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जुड़ जाएंगी जिसके परिणामस्वरूप इन सहकारी समितियों के सदस्य लघु और सीमांत किसान पहली बार नई पीढ़ी की बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.